श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। अब मुझे इस बारे मे कुछ नहीं कहना है।

श्री राम गोपाल यादव: श्रीमन् जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिलकुल दादागिरी की राजनीति करने लगा और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे साउथ एशिया इसके जागीर बन गई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कभी अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन ने कहा था...

"To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace."

जब दोनों ताकतें इस बात पर आमदा है कि किसी न किसी तरह से देश को अपमानित करें और जरूरत पड़ने पर आक्रमण भी कर सकती हैं तो क्या हमारा ऐटीच्यूड ऐसा होगा कि हम अपने को इतना सक्षम रखें कि उनका मुकाबला कर सकें?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, भारत हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे, इसी दृष्टि से पोखरन में परमाणु परीक्षण किया गया था। चीन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से जो कुछ कहा है वह नितान्त आपत्तिजनक है। हम उसे अस्वीकार करते हैं। वर्तमान विश्व में इस तरह के तथाकथित संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्षिण एशिया के देश अपनी शान्ति-सुरक्षा बनाए रखने में समर्थ हैं और समस्याओं को आपस में मिल बैठकर हल करने के लिए तैयार हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Extension of "Deemed Export" Benefits to new refineries

*424. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have extended "Deemed Export" benefits for equipment supplies to new refineries to be set-up in the Ninth Five Year Plan;

(b) whether these benefits are being given to all items imported by the oil and gas sector; and

(c) whether these benefits are applicable to foreign companies only or joint ventures also?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir; for the oil and gas sector (excluding refineries), in addition to equipment supplies to new refineries coming up in the Ninth Five Year Plan, deemed export benefits are available for domestic supplies of eligible capital goods to on-shore and off-shore oil and gas exploitation and exploration projects.

(c) Demand Export benefits are available in respect of supplies of domestically manufactured goods without reference to the suppliers' equity structure.

Opening of additional consulate in Dammam

*425. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government would take measures to strengthen the Indian Missions in various countries in the Gulf region in order to equip them to handle expatriate problems; and

(b) whether Government would take steps to open one additional consulate in Dammam in view of the heavy workload in the Indian Embassy at Riyadh and consulate office at Jeddah?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) and (b) The Ministry regularly sends teams of Foreign Service Inspectors to the Gulf region who supervise the working of the Missions and the workload and make recommendations with regard to staff strength. The Government has recently sanctioned 67 additional posts at various missions in the region.

2. The Government of Saudi Arabia generally does not permit the setting up of Consulates in Dammam. However, our Mission in Riyadh sends Consular teams every week to Dammam to provide passport and consular services to the Indian community in the area. These teams provide 375-400 consular services during each visit. Compared to other diplomatic missions in Saudi Arabia having large-size communities in the Kingdom, these weekly visits of consular teams are the most frequent.

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं

*426. **श्री राधाकिशन मालवीय:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में वर्ष 1997-98 के दौरान बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है;

(ग) क्या सरकार ने वहां हुई जान और माल की हानि के संबंध में भी कोई आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में कुल कितनी हानि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1997-98 के दौरान मंई, 1997 में आए भूकम्प, अगस्त, 1997 में आई बाढ़ और अक्तूबर, 1997 से मार्च, 1998 तक हुई ओलावृष्टि एवं शीतकालीन वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के बहुत से हिस्से अलग-अलग रूप से प्रभावित हुए।

इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण सम्पत्ति को हुए नुकसान की मात्रा तथा जान-माल की क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1997-98 के दौरान ओलावृष्टि, भारी वर्षा, बाढ़ और भूकम्प के कारण हुई क्षति।

क्रम सं०	आपदा	घटित होने की अवधि	फसलों को क्षति (लाख हैक्टे० में)	मकानों/झोपड़ियों को नुकसान (लाख में)	मृतक व्यक्ति (संख्या)	मृतक पशु (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1.	भूकम्प	22.5.1997	सूचना प्राप्त नहीं हुई	3.61	39	47
2.	बाढ़/भारी वर्षा	अगस्त-सितम्बर, 1997	0.38	0.48	34	1236
3.	भारी वर्षा	अक्तूबर—दिसम्बर, 1997	48.50	सूचना प्राप्त नहीं हुई	सूचना प्राप्त नहीं हुई	सूचना प्राप्त नहीं हुई
4.	ओलावृष्टि	अक्तूबर, 97—फरवरी, 98	4.45	1.04	36	641
5.	ओलावृष्टि	मार्च, 98	2.17	0.36	28	1265
	कुल:		55.50	5.49	137	3189